प्रेषक,

डी०पी० गैरोला, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

महाधिवक्ता. उत्तराखण्ड. मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर् नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादूनः दिनांकः 10 अप्रैल, 2013

विषय- मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध अधिवक्ताओं की देय फीस दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-67/XXXVI(1)/2010-43-एक (1) / 2003 दिनांक 25.03.2010 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल,शासन द्वारा मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध विधि अधिकारियों को दिनांक 01.01.2013 से निम्नलिखित दरों पर भुगतान किये जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

रिटेनर फीस

- स्थायी अधिवक्ता / शासकीय ₹ 10,000 / − (₹ दस हजार मुख्य अधिवक्ता
- मुख्य स्थायी अधिवक्ता / अपर ₹ 6,500 / − (₹ छ: हजार अपर शासकीय अधिवक्ता
- अधिवक्ता / उप शासकीय ₹ 5,000 / − (₹ पांच हजार स्थायी अधिवक्ता / सहायक शासकीय अधिवक्ता

बहस हेतु फीस

- मुख्य स्थायी
- अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता/अपर ₹ 2,500/- (₹ दो हजार शासकीय अधिवक्ता
- अधिवक्ता / उप अधिवक्ता / सहायक शासकीय अधिवक्ता
- वादधारक

मात्र) प्रतिमाह

पांच सौ मात्र) प्रतिमाह

मात्र) प्रतिमाह

अधिवक्ता / शासकीय ₹ 3,000 / - (₹ तीन हजार मात्र) प्रति कार्यदिवस

पांच सौ मात्र) प्रति कार्यदिवस

शासकीय ₹ 2,000/- (₹ दो हजार मात्र) प्रति कार्यदिवस

> ₹ 1,500 / - (₹ एक हजार पांच सौ मात्र) प्रति कार्यदिवस

> > कमश:-2

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013—14 के आय व्ययक के अनुदान सं0—04 के अधीन लेखाशीर्षक 2014—न्याय प्रशासन—00—आयोजनेत्तर—114—विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)—03—महाधिवक्ता—00—16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामें डाला जायेगा।
3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0—03 NP/XXVII(5)/13-14 दिनांक 05.04.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डीoपीo गैरोला) प्रमुख सचिव

संख्या-128 (VXXXVI(1) / 2012-43 एक(1) / 2003 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- 2- महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 4- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- गार्ड फाईल / एन०आई०सी०।

आज्ञा से

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी) संयुक्त सचिव